भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *55

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु कदम

***55. श्री रविन्दर कुशवाहा:**

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में कोयले के आयात को नियंत्रित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोयले के आयात की निर्भरता को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु कदम' के संबंध में श्री रविन्दर कुशवाहा तथा श्री हँसमुखभाई एस. पटेल द्वारा दिनांक 06.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *55 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : मौजूदा आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदात्मक करार के अनुसार अपनी पसंद के स्त्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2022-23 के दौरान, भारत में कोयला उत्पादन 893.19 मि.ट. था, जिसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.77% की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 2023 तक कोयला उत्पादन 591.40 मि.ट. रहा, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि दर्ज की गई।

इसके अलावा, चालू वर्ष 2023-24 में सितंबर, 2023 महीने तक कोयले का आयात 125.21 मि.ट. था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5% कम है। यदि नीलामी मोड/वाणिज्यिक कोयले की नीलामी के माध्यम से उत्पादन शुरू नहीं किया गया होता, तो सीएजीआर वृद्धि दर के अनुसार हमें 150.00 मि.ट. कोयले का आयात करने की आवश्यकता होती, लेकिन हमने वास्तव में अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 23-24 के दौरान केवल 125.21 मि.ट. कोयले का आयात किया है।

कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:

i. घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने की कुंजी है। वर्ष 2022-23 में, कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% से अधिक की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1012.14 मिलियन टन है। इसी तरह, 2025-26 में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अकेले एक बिलियन टन का उत्पादन करेगी।

ii. उन मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता के 90% तक (गैर-तटीय) तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% तक (तटीय विद्युत संयंत्र) तक कम कर दिया गया था, एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

iii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री हेतु अल्पावधि के लिए या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में कोयला लिंकेज

प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले और गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

iv. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

v. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की नौ बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

***